SHRI RAJESH PILOT: Mr. Chairman, if *you* permit me, I will----------

MR. CHA1RMAN: If both of you decide then you can take the whole time of the House. Question No. 424.

424. *[The questioner (Shri Suresh Kalmadi) was absent for answer* vide *col* 32 infra]

*425. *[The questioners (Shri Ranjit Singh and Shri Ravi Jethmalani) were absent. For answer* vide *col.* 33 infra]

Indian Telecommunication Technology *to* Bangladesh

*426. SHRIMATI VEENA VERMA: †
SHRIMATI BASANTI SARMA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have offered telecommunication technology to Bangladesh to upgrade the telecom system in that country; and

(b) if so, what are the detials in this regard?

THE MINISTER OP STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI RAJESH PILOT); (a) No, Sir, there was no such proposal for sharing telecommunication technology.

(b) Does not arise in view of answer to (a) above.

SHRIMATI VEENA VERMA: Sir, I am surprised at the answer because reliable reports say that an offer was made at the Sixth Tndo-Bangla Telecommunication Operational Co-ordination Committee held in New Delhi. It was inaugurated by Shri G. T. Narayanan,

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Veena Verma.

Adviser (Operations) in the Telecommunication Commission. I would like to know whether this report is correct. I would like to know what was the subject that was discussed at this meeting and whether the subject of co-operation in telecommunication field was discussed between the two countries.

SHRI RAJESH PILOT: Mr. Chairman, Sir, what the hon. Member is saying is a fact that this meeting did take place. But there was no offer from our side for technology transfer. Neither technology transfer nor any such thing was discussed. We discussed about something like telephone instruments because we are producing more than the requirement of our country. Some of those things were discussed if that country could buy telephone instruments, road traffic signals, ECV plants, etc. TheSe are not really concerned with technology transfer or technology offer. These are some things which are available with us and whether they can buy some telephone instruments from us, such a discussion took place and not technology transfer.

श्रीमती वीणा वर्मा : कुछ दिन पहले एक कमेटी, अथैया कमेटी सेट अप की गय थी । यदि हां, तो क्या दूसरे देशों को कम्युनिकेशन असिस्टेंस देने के बारे में कोई रिकमंडेशन दी गयी है, यदि हां तो वे रिकमंडेशन क्या हैं ?

श्री राजेश पायलट : यह वास्तविकता है कि अथैया कमेटी बैठायी गयी थी । उन्होंने रिकमंडेशन भी दी है । सरकार उस पर विचार कर रही है ।

SHRI KAPIL VERMA: At present there is an Indo-Bangla micro-wave link. I would like to know whether the Government is considering any proposal to upgrade it into a digital system.

SHRI RAJESH PILOT: Sir, I require a separate notice for full details on this particular project.

SHRI KAPIL VERMA: I would lute to know whether the Government Is considering it or not.

SHRI RAJESH PILOT: Sir, I requite notice for getting the correct information.

Child Welfare Schemes

*427. SHRI SURESH PACHOURI: WU1 the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to spend Rs. 35 crores for the various child welfare Schemes during the next one year and if so, the details thereof; and

(b) whether Government have prepared estimates for the investments needed for meeting the challenge of child welfare, and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE ENVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) \!*TH ADDITIONAL CHARGE OF MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF-WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (KUMARI MAMATA BANERJEE): (a) and (b) The Government have prepared estimates which have been sent to\the Planning Commission. These estimates have not yet been finalised. It is hoped that the amount spent on Child Welfare Schemes for 1992-93 will be much higher than Rs. 35 crores and would cover expenditure on JCDS Creches and Adolescent Girls among other things.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, आदरणीय मंत्री महोदय, ने चाइल्ड वेल्फेयर स्कीम्स के तहत जो एक्सपेंडीचर है उसमें आई०सी०डी०एस० को भी कवर करने का अपने उत्तर में उल्लेख किया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि आई०सी०डी० एस० के अंतर्गत कितने बच्चे व गर्भवती महिलायें लाभांवित हुए हैं । आई०सी०डी० एस० प्रोग्राम कितने ब्लाक्स में चल रहा है ? सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितने रुपए व्यय किए गए तथा वर्ष 1991–92 के लिए, कितने बजट का प्रावधान इनके मंत्रालय ने रखा है ? जितने ब्लाक्स में आई०सी०डी०एस० प्रोग्राम चल रहा है, उनमें मध्य के कितने ब्लाक शामिल हैं?

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति महोदय, आई०सी०डी०एस० प्रोग्राम हमारे डिपार्टमेंट का सब से बड़ा प्रोग्राम बाल कल्याण के लिए है । इस प्रोग्राम में 1.29 करोड चिल्ड्रन जीरो टू सिक्स ईयर्ज और 27.20 लाख प्रेगनेंट वूमेन लाभान्वित हुए हैं । हमारे पूरे देश में इसके लिए 2594 स्वीकृत ब्लाक्स हैं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 850 करोड रुपया इसके लिए खर्च हुआ है । 1991–92 का बजट 307 करोड़ का है । वर्ल्ड बैंक भी इसके लिए हम को मदद देता है । हम पूरे मध्य प्रदेश को कवर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं । जो 2594 ब्लाक्स का प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है, इसके बाद संसद सदस्य चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को सब डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेंड किया जाए । इसलिए हमारी कोशिश यह है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में हम इसे एक्सपेंड करेंगे ।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कीम है, उसके अंतर्गत नान आई०सी०डी०एस० एरियाज में इस स्कीम को जारी करने संबंधी घोषणा इनके मंत्रालय ने की थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो एजूकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स हैं उनमें इसको प्रारंभ किया जाएगा । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कीम में जो एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट्स ली गई हैं, उनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और यदि है तो उसको कितनी असिस्टेंस दी जाएगी ? साथ ही वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस जो इन कार्यक्रमों के लिए दी जा रही है उसके अंतर्गत क्या मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है, यदि किया गया है तो मध्य प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की जाएगी ?

कुमारी ममता बनर्जी : सभापति जी, नान आई०सी०डी०एस० एरिया जो हैं